

भारत-जापान इस्पात वविाद

समाचारों में क्यों ?

हाल ही में जापान ने डब्ल्यूटीओ (वश्व व्यापार संगठन) से अनुरोध किया है कि वह भारत-जापान इस्पात वविाद की सुनवाई तय समय से पहले करने पर वचिार करे, जिसका कि भारत ने पुरजोर वरिोध किया है। वदिति हो कि जापान ने इस्पात के व्यापार के संबंध में भारत के साथ हतियों के टकराव को लेकर डब्ल्यूटीओ (वश्व व्यापार संगठन) से इसका हल नकिलने को कहा है। आमतौर पर बातचीत से वविाद हल करने वाले जापान की ओर से उठया गया यह कदम सबको हैरान कर रहा है।

क्या भारत-जापान इस्पात वविाद ?

जापान का आरोप है कि पिछले एक साल से भारत में उसका इस्पात का नरियात आधा हो गया है क्योंकि भारत ने कुछ प्रतबिंध लगा रखे हैं। गौरतलब है कि इस पूरे वविाद को दुनियाभर में व्यापार वविादों की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। जापान को आमतौर पर आक्रामक प्रतिक्रियाएँ करते नहीं देखा गया है, इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक यह देश वविादों को बातचीत से हल करने का पक्षधर रहा है लेकिन इस्पात जापान के वैश्विक उद्योग का अहम हस्सा है। जापान के कुल नरियात में इस्पात का हस्सा 50 प्रतिशत का है।

जापान, भारत में अपने घटते लौह-इस्पात के नरियात को लेकर चतिति है, गौरतलब है कि भारत ने सतिंबर 2015 में कुछ इस्पात उत्पादों पर 20 प्रतिशत की ड्यूटी लगा दी थी और फरवरी 2016 में उसने इस्पात के आयात के लिये एक न्यूनतम मूल्य नश्चिती कर दिया ताकि जापान, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश भारत के लौह-इस्पात उद्योग में संध न लगा पाएँ। इस संबंध में जापान ने डब्ल्यूटीओ से 20 दसिंबर को सलाह मांगी थी। जापान का कहना है कि भारत का कदम वश्व व्यापार संगठन के नयिओं के वपिरीत है और इस कारण से भारत में उसका नरियात गरिा है।

जापान जहाँ 2015 में भारत को लौह-इस्पात का नरियात करने वाला छठा सबसे बड़ा देश था वही नवंबर 2016 में यह 10वें स्थान पर आ गया था।

नश्चिर्ष

भारत ने इस्पात पर न्यूनतम आयात शुल्क इसलिये लगाया था क्योंकि चीन, जापान और कोरिया जैसे इस्पात अधशेष वाले देशों से बाज़ार बगिाड़ने वाले मूल्य पर इस्पात का आयात सतिंबर 2014 से घरेलू उद्योग के लिये चतिता का वषिय बना हुआ है। भारत ने घरेलू कंपनयियों को सस्ते आयात से संरक्षण के लिये कुछ इस्पात उत्पादों पर डंपगि रोधी शुल्क भी लगाया है।

दरअसल, लौह-इस्पात को लेकर दुनियाभर में व्यापारिक वविाद बढ़ रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक चीन ने बेहद सस्ती कीमतों पर लौह-इस्पात का नरियात किया है। इस कारण वयितनाम, मलेशया और दक्षिण कोरिया ने उस पर पाबंदी लगा दी थी। नतीजतन चीन का नरियात 2016 में 3.5 प्रतिशत तक गरि गया था। भारत भी नहीं चाहता कि वविादों से आने वाले सस्ते इस्पात से उसका घरेलू बाज़ार पट जाए, इसी को ध्यान में रखकर भारत ने इस्पात उत्पादों पर शुल्क लगाया है।

जहाँ डब्ल्यूटीओ के माध्यम से वविादों के नपिटारे का सवाल है भारत को इसके लिये कमर कस लेना होगा क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार संधयियों को तोड़ने और भारी भरकम आयात कर लगाने की बातें कही हैं उससे डब्ल्यूटीओ में व्यापारिक वविादों का सैलाब देखने को मलि सकता है।